जनसत्ता

कूटनीतिक कामयाबी

संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। यानी अब मसूद और उसका संगठन उस काली सूची में आ गया है जिसमें दुनिया के लिए खतरा बने आतंकी संगठन और उनके सरगनाओं को रखा जाता है। भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के लिए लंबे समय से जारी भारत की कोशिशों में चीन बड़ी बाधा बना हुआ था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चीन पर सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने जिस तरह से दबाव बनाया, उसी से अंततः भारत को यह कामयाबी मिली। मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए सुरक्षा परिषद में जितनी बार भी प्रस्ताव लाए गए, चीन हमेशा उन्हें वीटो कर देता था। मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान भी बेनकाब हो गया है। इससे यह साबित हुआ है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे कई आतंकी संगठनों की जन्मस्थली है और आतंक का सारा कारोबार उसकी जमीन से संचालित होता है। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आइएसआइ की मदद से ही ये आतंकी संगठन भारत सहित दूसरे देशों के लिए सरदर्द बने हुए हैं।

मसूद के मामले में सुरक्षा परिषद में ताजा प्रस्ताव पुलवामा आतंकी हमले के बाद लाया गया था। अमेरिका ने मसौदा पेश किया था और फ्रांस, ब्रिटेन ने इसका समर्थन किया था। पुलवामा हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के चवालीस जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। मसूद अजहर लंबे समय से भारत के लिए वांछित है। मुंबई हमले से लेकर पठानकोट, उड़ी और नगरोटा में सैन्य और नागरिक ठिकानों पर आतंकी हमलों का साजिशकर्ता मसूद अजहर ही रहा है। मसूद अजहर को सबसे पहले 1994 में कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कंधार अपहरण कांड के बाद हुई सौदेबाजी में भारत सरकार ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद वह पाकिस्तान में जा बसा और भारत के खिलाफ मुहिम चलाता रहा। भारत पर जब-जब आतंकी हमले हुए, जांच एजेंसियों ने पूरी जांच के बाद पुख्ता सबूत जुटाए और पाकिस्तान को सौंपे। लेकिन पाकिस्तान इन सबूतों को तो दूर, मसूद अजहर की अपने यहां मौजूदगी तक को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान घिर गया और उसने यह स्वीकार किया कि मसूद उसके यहां है।

चीन शुरू से ही मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के खिलाफ रहा है। दरअसल, चीन और पाकिस्तान के रिश्ते जगजाहिर हैं। पाकिस्तान में उसके कारोबारी हित हैं। चीन-पाक आर्थिक गलियारा सबसे बड़ी परियोजना चल रही है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकता। हालांकि मसूद अजहर के मसले पर चीन के रुख में बदलाव अमेरिका के भारी दबाव और हाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ हुई मुलाकात के बाद आया है। पिछले महीने ही पहली बार चीन ने यह माना था कि मुंबई का आतंकी हमला दुनिया के सबसे भीषण और कुख्यात हमलों में से एक था। तभी से चीन पर दबाव के संकेत मिलने लगे थे। मसूद अजहर अब वैश्विक आतंकी घोषित तो हो गया, लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसे पाकिस्तान से लाने की है। मसूद को काली सूची में डाल दिए जाने के बाद पाकिस्तान को अब किसी सबूत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान शांति चाहता है और इसके लिए भारत एक कदम बढ़े तो वह दो कदम बढ़ने को तैयार है। तो अब मौका है जब इमरान खान पहल करें और मसूद सहित जिन-जिन आतंकियों को भारत मांग रहा है, उन्हें भारत के हवाले करें।

हमला और सवाल

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बुधवार को नक्सलियों के हमले में पुलिस के पंद्रह जवानों की मौत चिंताजनक है। साफ है कि हालात काबू में नहीं हैं और नक्सली पूरी ताकत के साथ हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वे आए दिन वाहनों को फूंक रहे हैं, सड़क बनाने में लगी मशीनों को आग के हवाले कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। क्या ये सब मामूली घटनाएं हैं? क्या सरकार के लिए यह गंभीर चुनौती नहीं है? सवाल है कि अगर सब कुछ नियंत्रण में है और सरकार नक्लसियों से निपटने में सफल रही है, जैसा कि हमेशा दावा किया जाता रहा है तो फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? इससे तो लगता है सरकार का खुफिया तंत्र नाकाम है और उसे नक्सलियों के हमलों की भनक तक नहीं लगती। लेकिन बुधवार के इस दहला देने वाले हमले के बाद महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक ने खुफिया नाकामी की बात से साफ इनकार कर दिया। सवाल है कि अगर जरा भी खबर होती कि नक्सली आइईडी से हमला करने वाले हैं तो क्या जवानों को ले जा रहा वाहन वहां से गुजरने दिया जाता! सच यह है कि नक्सलियों ने यह हमला करके खुफिया तंत्र की पोल खोल दी है।

गढ़चिरौली जिले में जहां यह हमला हुआ है वह जगह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की सीमा से सटा इलाका है। नक्सलियों ने हमले से कुछ घंटे पहले इस इलाके में एक सड़क निर्माण ठेकेदार की मशीनों और वाहनों को आग लगा दी थी। इसकी खबर मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के कमांडो दो बसों में सवार में होकर मौके पर जा रहे थे। तभी नक्सलियों ने बारूदी सुरंग को उड़ा डाला। नक्सली इन इलाकों में निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। उन्हें इस बात का खौफ है कि सड़कों का नेटवर्क खड़ा हो जाने के बाद उनके खिलाफ सुरक्षाबलों के अभियान तेज हो जाएंगे। बुधवार को हमले के वक्त मौके पर करीब दो सौ नक्सली मौजूद थे। हालांकि पिछले साल अप्रैल में पुलिस ने चालीस नक्सलियों को मार गिराया था। तब सरकार ने दावा किया था कि नक्सली अब सिर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन एक साल बाद फिर से नक्सलियों ने बड़ा हमला कर अपनी मौजूदगी और ताकत का संदेश देने की कोशिश की है। पिछले महीने दस तारीख को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक भाजपा विधायक और चार पुलिस वालों की हत्या कर दी थी।

दो साल पहले माओवादी हिंसा से प्रभावित दस राज्यों में एकीकृत कमान के गठन की पहल भी हुई थी और सभी राज्यों की साझा रणनीति बना कर आठ सूत्री समाधान भी तैयार किया गया था। लेकिन बुनियादी समस्या यह है कि नक्सलवाद से निपटने की योजनाएं जिस प्रभावी तरीके से लागू होनी चाहिए, लगता है वे हो नहीं रहीं। सत्ता तंत्र के इस रवैए से लगता है कि वह इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ऐसे में सारी कवायद निष्फल साबित होती है। इसमें पैसा और समय तो जाता ही है, समस्या और गहराती जाती है। नक्सल समस्या दशकों पुरानी हो चुकी है। अगर इतने सालों में भी पिछड़े इलाकों में विकास नहीं हो पाया है और नक्सलियों का दबदबा बना हुआ है तो इसके लिए सीधे-सीधे राज्य और केंद्र सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर नक्सलियों की समांतर सत्ता कायम है तो यह उनकी कामयाबी से कहीं ज्यादा हमारे शासन तंत्र की नाकामी का सबूत है। वरना ऐसे बड़े हमले बार-बार नहीं होते!

कल्पमेधा

जीवन में जो कुछ पवित्र और धार्मिक है, स्त्रियां उसकी विशेष संरक्षिकाएं हैं।
-महात्मा गांधी

ऊर्जा में थोरियम का विकल्प

अभिषेक कुमार सिंह

भारत का यूरेनियम भंडार दुनिया के भंडारों के मुकाबले एक फीसद से कम है, लेकिन इसके मुकाबले हमारा थोरियम भंडार दुनिया के भंडारों के मुकाबले अड़सठ फीसद अधिक है। एक तथ्य यह भी है कि थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर बना कर भारत अगले चार सौ साल तक अपनी जरूरतों के मुताबिक ऊर्जा पा सकता है।

किसी भी विकासशील देश की तरह भारत को भी अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए। सरकार के दावे पर यकीन करें तो अब देश के अठारह हजार गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई है और शहरों में बिजली की खपत में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ही इस साल यह खपत सात हजार मेगावाट प्रतिदिन पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है जो इस साल मई-जून में किसी भी दिन सच साबित हो सकता है। हालात ऐसे हैं कि एक ही महानगर को बिजली देने के लिए कई बिजलीघरों को एक साथ चलाना पड़ रहा है। वैसे तो बिजली पैदा करने के कई अलग-अलग विकल्प हैं, पानी से पनबिजली पैदा की जा रही है, तो तेल-गैस और कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्र भी देश में हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर देखें तो 2024 तक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन तीन गुना करने या दीर्घकालिक लक्ष्य के मुताबिक एटमी ऊर्जा से देश में पैंतीस हजार मेगावाट बिजली पैदा करने के लक्ष्य हमें मजबूर करते हैं कि देश अपना सारा जोर एटमी बिजली पैदा करने में लगाए।

दो साल पहले 2017 में पोकरण परीक्षण की वर्षगांठ के मौके पर सरकार ने घोषणा की थी कि देश में स्वदेशी तकनीक पर आधारित दस नाभिकीय रिएक्टर (परमाणु संयंत्र) लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों से सात हजार मेगावाट बिजली हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इन संकल्पों के समांतर हाल में खबर यह भी आई है कि जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टरों के निर्माण का ठेका पाने वाली फ्रांस की कंपनी ईडीएफ ने परियोजना के वित्त पोषण के लिए भारत को फ्रांस की दो अन्य सरकारी कंपनियों को संप्रभु गारंटी उपलब्ध कराने की शर्त रखी है। ईडीएफ ही वह कंपनी है जो महाराष्ट्र के जैतापुर में भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित करेगी। इसमें 1650-1650 मेगावॉट क्षमता के छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होंगे। कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में ही भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआइएल) को एक प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक पेशकश की थी। इस पेशकश पर सरकार ने हाल तक कोई जवाब नहीं दिया है। यह चुप्पी असल में बहुत कुछ कहती है।

परमाणु संयंत्रों को ईंधन मुहैया कराना अब भी टेढ़ी खीर है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता की राह में चीन अड़ंगा है, तो अमेरिका सहित कई अन्य देश करार के बावजूद परमाणु सहयोग करने को आसानी से राजी नहीं होते हैं। अतीत में ऐसा कई बार हुआ है, जब परमाणु संयंत्रों के ईंधन के रूप में यूरेनियम की सप्लाई को अमेरिका-आस्ट्रेलिया सहित कई देश झटके दे चुके हैं। साफ है कि हमारे देश को विदेशों से यूरेनियम की आपूर्ति की राह कठिन है। असल में, झगड़े की जड़ यूरेनियम की सप्लाई ही है जिसे लेकर हमेशा संदेह बने रहते हैं। यही नहीं, समझौतों के बल पर यदि जरूरत भर का ईंधन मिल भी गया, तो भी सिर्फ दिल्ली के लिए ही सात हजार मेगावाट बिजली बनाने के लिए हर साल कई हजार टन बेहद महंगा यूरेनियम खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। यह सारी कसरत उस वक्त भी बेकार लगती है जब एटमी एनर्जी के मामले में एक सवाल आत्मनिर्भरता का उठता है।

सात साल पहले 2012 में जब तमिलनाडु में रूस की मदद से स्थापित कुडनकुलम परमाणु संयंत्र को चालू करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इसे लेकर उठे विरोध के बीच कुछ विश्लेषकों ने सवाल उठाया था कि भारत आखिर क्यों नहीं यूरेनियम की बजाय थोरियम वाले विकल्प पर गौर करता है जो न केवल सुरक्षित है, बल्कि भारत को परमाणु ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर भी बना सकता है। भारत का यूरेनियम भंडार दुनिया के भंडारों के मुकाबले एक फीसद से कम है, लेकिन इसके मुकाबले हमारा थोरियम भंडार दुनिया के भंडारों के मुकाबले अड़सठ फीसद अधिक है। एक तथ्य यह भी है कि थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर बना कर भारत अगले चार सौ साल तक अपनी जरूरतों के मुताबिक ऊर्जा पा सकता है।

इसमें एक बाधा यह है कि थोरियम से चलने वाले रिएक्टर बनाने में करीब पांच दशक तक लग सकते हैं। दूसरे, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अकेले थोरियम से बिजली नहीं बनाई जा सकती क्योंकि थोरियम ऐसा तत्त्व नहीं है जो सीधे यूरेनियम की जगह ले सके। इसके लिए उसमें प्लूटोनियम मिलाते हुए इन दोनों तत्त्वों का 20-80 का अनुपात (20 फीसद यूरेनियम, 80 फीसद थोरियम) रखना होगा। एक वक्त था जब देश में थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा की दिशा में काफी सोच-विचार चला था। जब से अमेरिका-भारत परमाणु समझौते की बात शुरू हुई थी, तभी से यह जोर-शोर से कहा जाने लगा था कि क्यों नहीं भारत उस परमाणु ईंधन के बारे में सोचता, जिसके लिए उसे अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) की कड़ी शर्तों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा।

यहां कुछ अहम सवाल हैं। पहला यह कि क्या दुनिया में कहीं और थोरियम आधारित परमाणु संयंत्रों से बिजली पैदा की जा रही है? दूसरे, इस तरह के संयंत्रों में पैदा की जाने वाली बिजली बहुत महंगी तो नहीं हो जाएगी? इस बारे में कुछ प्रयोग फ्रांस, अमेरिका समेत कई विकसित देशों ने किए, पर उनमें सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने इससे हाथ खींच लिए। लेकिन हमारे देश के परमाणु वैज्ञानिकों ने थोरियम रिएक्टरों के मामले में काफी सफलता पाई है। चेन्नई के पास कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (आइजीसीएआर) में थोरियम आधारित बिजली उत्पादन कार्यक्रम पर काफी समय से शोध चल रहा है। वहां पांच सौ मेगावाट का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने का काम भी चल रहा है। चेन्नई स्थित एडवांस्ड थोरियम ब्रीडर रिएक्टर में आठ सौ अस्सी किलो प्लूटोनियम डालने के बाद ग्यारह सौ किलो थोरियम यूरेनियम-233 में बदल जाएगा। इस तरह इस रिएक्टर में जितने ईंधन की खपत की जाएगी, उससे अधिक ईंधन पैदा हो जाएगा। इसके अलावा विश्लेषकों का कहना है कि पंद्रह साल पहले अक्तूबर, 2004 में कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो निर्माण कार्य शुरू किया गया था, अगर उसमें पर्याप्त सफलता मिलती है तो भारत अपनी मौजूदा राष्ट्रीय बिजली उत्पादन क्षमता से तीन गुना अधिक उत्पादन यानी साढ़े तीन लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन स्वदेशी परमाणु सामग्री और तकनीक से कर सकेगा।

यह भी दावा है कि यह थोरियम रिएक्टर दुनिया के किसी भी अन्य रिएक्टर से ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा थोरियम आधारित ऐसे परमाणु बिजलीघर में एक बार ईंधन डालने के बाद दो साल तक और ईंधन की जरूरत नहीं होती है। सबसे खास बात यह कि इस रिएक्टर में न तो प्राकृतिक यूरेनियम की जरूरत पड़ती और न ही संवर्धित यूरेनियम की। और जहां तक सैन्य उद्देश्यों के लिए (यानी एटमी हथियारों के लिए) प्लूटोनियम और यूरेनियम की जरूरत का सवाल है, तो यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अमेरिका से समझौते के बाद भी भारत आयातित यूरेनियम से निकले प्लूटोनियम का इस्तेमाल इस मकसद में नहीं कर पाता है। इसके उलट अगर वह थोरियम रिएक्टरों पर अपनी निर्भरता बढ़ाता है, तो इन संयंत्रों से निकले यूरेनियम का इस्तेमाल अपनी मर्जी से सैन्य उद्देश्यों के लिए भी करने को स्वतंत्र होगा। स्पष्ट है कि यूरेनियम-थोरियम के बीच थोरियम एक श्रेष्ठ विकल्प है। साथ ही, भारत अपने यहां विकसित थोरियम तकनीक पर पेटेंट अधिकार ले सकता है, यानी आगे चलकर दुनिया इसकी नकल नहीं कर सकती। इसीलिए मूल सवाल यही है कि क्यों नहीं इस बारे में राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई जाती है और अंतरराष्ट्रीय निगरानी व यूरेनियम आयात की कड़ी शर्तों पर स्वदेशी थोरियम आधारित परमाणु संयंत्रों के विकास को तरजीह दी जाती?

सड़क पर जिंदगी

हरिंदर राणावत

दुनिया मेरे आगे

बसों के घरघराते इंजन की आवाजों, रह-रह कर बज उठते हॉर्न और प्रतीक्षा में खड़े मुसाफिरों के बीच से होता हुआ वह हमारे सामने आकर रुका और फिर वहीं बैठ गया। अंतरराज्यीय बस अड्डे के ठंडे फर्श पर बैठा हुआ वह आदमी हमारी ओर यों देख रहा था जैसे पुरानी जान-पहचान हो। उसका एक पैर घुटनों के ऊपर से कटा हुआ था। देश की सड़कों-गलियों में हजारों लोगों की तरह वह भी शायद भीख मांग कर गुजारा करने वालों से एक था। वहीं चाय की दुकान में चाय का ऑर्डर वह शायद पहले ही देकर आया था, क्योंकि एक लड़का चाय से भरा प्लास्टिक का कप उसके पास रख गया था।

चाय पीने की शायद उसे कोई जल्दी नहीं थी। स्लेटी रंग की ठंडी टाइलों वाले फर्श पर कप ज्यों का त्यों पड़ा था। धूसर-मटमैले और कई जगह से कटे-फटे कोट के भीतर हाथ डाल कर उसने कुछ टटोला, फिर सिगरेट और माचिस निकाल ली। 'कल शाम को ही दस पुड़िया लेकर आया हूं। पांच सौ रुपए की।' सिगरेट सुलगाते हुए उसने जैसे बात शुरू करने के लिए कहा। मैल से चीकट उसका चेहरा माचिस की लौ में निमिष भर के लिए चमका। एक बेंच पर बैठे हम कुछ मुसाफिरों में एक साधु भी था। उसे देख कर शायद उसे लगा हो कि कोई और उसकी बातें सुने या न सुने, साधु बाबा तो सुन ही लेंगे। इसलिए वह बोले जा रहा था। सिगरेट के लंबे कश से उठे धुएं के छल्ले उसके चेहरे के सामने से होते हुए ऊपर उठे और हवा में विलीन हो गए।

कुछ देर वह अपनी पुड़िया के बारे में बताता रहा कि दो पुड़िया आज रात को लेगा। एक कल सुबह उठ कर। साधु ने उसे हीन दृष्टि से देखते हुए कहा- 'स्मैक पर रुपए क्यों बर्बाद करते हो? अच्छी चीजें खाओ।' फिर जैसे साधु को याद आया तो कहा- 'घी खाओ'। घी कहते हुए शुद्ध देसी घी की सुगंध जैसे साधु के भीतर गहरे तक उतर गई। भिखारी ने शायद साधु की आंखों में अपने लिए हीन भाव भांप लिए थे। अपने भीतर उच्चता बोध समेट कर वह ऊंचे स्वर में बोला- 'अरे मैं पांच सौ रुपए रोज कमाता हूं। पचास रुपए में एक पुड़िया आती है। अभी तो मैं बाराबंकी वाली लेता हूं। यह थोड़ी सस्ती है। लेकिन अपना काम चल जाता है।' साधु समझ गया था कि भिखारी को घी का महत्त्व समझाना टेढ़ी खीर साबित होगा।

खैर, वह भिखारी फिर हमसे मुखातिब हो गया- 'कल का रविवार खराब हो गया। अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो पांच-छह सौ तो मैं पक्का बना लेता। लेकिन पैर में दर्द इतना था कि मैंने कहा छोड़ो। कल रात को दवा ली थी। आज तीन टिकिया लेनी है।' उसने अपनी नेकरनुमा पैंट अपने कटे पैर से ऊपर उठाई। वहां अधपका घाव साफ नजर आ रहा था। उसने कहा- 'मैं सोचता रहा कि यह चोट कैसे लग गई! बाद में याद आया कि दो रोज पहले रात को मैं यमुना के पुल पर सो रहा था। आधी रात पुलिस वाले ने बड़े जोर से डंडा मार कर जगाया था। डॉक्टर ने दवा लिख कर दी। तीस रुपए की दवा आई है।'

पैर कैसे कटा, यह बताने से पहले उसने यह बताना जरूरी समझा कि किसी की बददुआ की वजह से पैर कटा। 'साहब, मैं ट्रेन में जेब काटता था। किसी की बददुआ ही लगी होगी कि मेरा पैर कट गया। उस दिन भी एक बंदे की जेब काट कर मैं दूसरे डिब्बे में दरवाजे पर पैर लटकाए बैठा था। स्मैक की खुमारी चढ़ी हुई थी। हवा लगने से नशा और तेज हो गया था। फिर तेज दर्द के साथ नशा टूटा। सिर्फ अपने चीखने की याद है। अलीगढ़ के पास यह हादसा हुआ। फिर अस्पताल में ही आंख खुली। जिसकी जेब काटी थी, उसके पर्स में से अट्ठाईस सौ रुपए मिले थे। वही जेब में थे। पुलिस से बाद में वे रुपए मिल गए। लेकिन पैर चला गया।' उसने बताया कि जो पुलिस वाला उसे अस्पताल लेकर आया था, उसने उसे कुछ पैसे भी देने की कोशिश की।

उसने बताया कि एक बार वह अपने गांव गया। वहां उसकी पत्नी और दो लड़के हैं। उसने आठवीं में पढ़ने वाले बड़े लड़के को फिल्म देखने के लिए पचास रुपए दिए थे, तो उसकी पत्नी ने आंखें तरेरते हुए कहा था- 'क्यों इनकी आदतें बिगाड़ रहा है। बाद में ये पैसे मांगेंगे तो मैं कहां से दूंगी।' बातें खत्म हुईं तो जाने की तैयारी करते हुए उसने कहा कि अब वह ऊपर लोकल अड्डे पर जाकर दो घंटे भीख मांगेगा। कम से कम दो सौ रुपए बना लेने हैं।

बेंच पर बैठे हममें से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह घृणा का पात्र था... सहानुभूति का... या दया का। व्यवस्था की नजर में उसकी जगह क्या है!

न्याय की भाषा

पटना उच्च न्यायालय ने हिंदी में याचिकाएं स्वीकार करने संबंधी निर्णय देकर एक ऐतिहासिक कार्य तो किया ही है साथ ही वर्षों से चल रहे संघर्ष का सम्मान भी किया है। हालांकि 1972 में ही राज्य सरकार ने हिंदी के उपयोग संबंधी अधिसूचना जारी कर राज्य में प्रचलित इस भाषा को उच्च न्यायालय में भी कतिपय मामलों में लागू करने का निर्देश जारी किया था लेकिन लालफीताशाही और प्रक्रियाओं की उलझनों ने इसके कार्यान्वयन को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उच्च न्यायालय के अभिलेख साक्षी हैं कि करीब दो दशक पूर्व न्यायाधीश सतीश चंद्र मिश्र ने हिंदी में न्यायिक निर्णय सुना कर इस भाषा के प्रति श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित किया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि पटना उच्च न्यायालय में प्रारंभ से हिंदी के जानकार न्यायाधीश पदस्थापित रहे हैं मगर अज्ञात कारणों ने उन्हें हिंदी में अपना फैसला देने से वंचित रखा गया है। खैर, जो बीत गई सो बात गई, अब न्यायालय के अन्य कार्य भी हिंदी में संपन्न किए जाएं इसकी सामयिक जरूरत है।

बिहार ही नहीं बल्कि अन्य सभी हिंदी भाषी राज्यों के न्यायालयों में भी हिंदी में सभी कार्य संपन्न हों इसके लिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग की सक्रियता आवश्यक है। हिंदी आज अपने घर में ही कैद है लेकिन उच्च न्यायालय के वर्तमान निर्णय से हिंदी प्रेमियों के हृदय में आशा और उत्साह का सूर्योदय हुआ दिखता है। मॉरीशस की यात्रा के दौरान पोर्टलुई हवाई अड्डे पर अंग्रेजी के साथ-साथ संकेत पट्टिकाएं हिंदी में भी लिखी हुई थीं जबकि अपने देश के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इसकी कमी दिखती है। गुड-मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के दैनिक अंग्रेजी के व्यवहार ने हमारे दिमाग को 'स्मार्ट' तो बना दिया है लेकिन हृदय-तल में विराजमान हिंदी के स्वर को कुंठित मुद्रा में ला दिया है।

आंकड़े गवाह हैं कि आज कई देशों में हिंदी की पढ़ाई, शोध, कार्यशाला नियमित रूप से संचालित हैं। अपने देश का जब 70 प्रतिशत भूभाग हिंदी भाषा से आच्छादित तो इसे मुख्यधारा का अंग बनाने के संकल्प से सभी हिंदी प्रेमियों को जुटना अनिवार्य लगता है। उच्चतम न्यायालय में भी हिंदी प्रयोग की प्रतिष्ठा मूर्त रूप ले इस ओर भी चेष्टारत होना जरूरी है और सरकारी सहयोग भी।

● *अशोक कुमार, पटना*

कार्रवाई का दायरा

चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुख्यमंत्री/ पूर्व मुख्यमंत्री सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं पर कार्रवाई कर उनके तुनाव प्रचार करने पर 24 से 72 घंटे की पाबंदी लगाई जो स्वागतयोग्य है। वैसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया द्वारा भी किया जा रहा है। सभी दलों के बड़े नेताओं के वक्तव्यों को दलों के कुशल प्रबंधन के आधार पर अनेक बार दिखाया जा रहा है या सीधा प्रसारण किया जाता है। बहुधा होता यह है कि नेताओं के भाषण में से सिर्फ उन्हीं बिंदुओं का प्रमुखता से प्रकाशन/ प्रसारण किया जा रहा है जिससे वैमनस्य/ विवाद फैले। कुल मिलाकर नकारात्मक बातें परोसी जा रही हैं। सिर्फ राजनीतिक दलों या उनके नेताओं पर कार्रवाई से साफ-सुथरे चुनाव नहीं होंगे, इसके लिए चुनाव आयोग को अपनी जद में सबको लेना होगा।

● *मिलिंद रोंघे, महर्षिनगर, इटारसी*

आगे की राह

यूपी बोर्ड ने पिछले दिनों हाइस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया। अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी कुछ ही दिनों में घोषित कर दिए जाएंगे। इन परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्र निराश न हों। आगे भी कई अवसर हैं। संयम रखते हुए आत्मविश्वास से आगे की राह देखनी चाहिए। परीक्षा परिणाम जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने या कम अंक आने की वजह से आत्महत्या जैसी बात तो सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। यह तो जीवन की एक सीढ़ी है, जिसके सहारे आगे बढ़ा जाता है। अगर किसी को सफलता किन्हीं कारणवश नहीं मिल पाई तो घबराने या हताश होने की बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में जिन छात्रों को किन्हीं कारणों से सफलता नहीं मिल पाई है, उन्हें हताश होने की बजाय आगे के मौके तलाशने चाहिए। असफल छात्र कंपार्टमेंटल या अगले वर्ष दोबारा परीक्षा देकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। असफल विद्यार्थी अपने आत्मविश्वास में कमी न आने दें। आत्मविश्वास में कमी से वे अवसाद के शिकार हो सकते हैं।

इस परिस्थिति में अभिभावकों को अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि परीक्षाओं के परिणाम आने के पहले बच्चों के व्यवहार में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन पर नजर रखें। अभिभावक अपने बच्चों को हताशा की बजाय सकारात्मकता से भर कर आगे के विकल्प तलाशने में मदद करें।

● *सुशील वर्मा, गोरखपुर विश्वविद्यालय*

गलत रवैया

अमेरिका ने घोषणा की है कि अगर कोई भी देश ईरान से तेल खरीदेगा या किसी भी तरह का रिश्ता रखेगा तो उसे अमेरिका से मिलने वाली सभी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी। दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच अभी तनाव चरम पर पहुंचा हुआ है लेकिन अमेरिका का ईरान से संबंध रखने वाले दूसरे देशों के प्रति यह रवैया बेहद गलत है। क्या सभी देशों की अर्थव्यवस्था एक जैसी होती हैं? अमेरिका को अपने व्यापार संबंधी मामलों को खुद सुलझाना चाहिए न कि अन्य देशों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। भारत में वैसे ही तेल की कीमत को लेकर हर समय सरकारें घिरती रहती हैं। अमेरिका के ऐसे कदम से भारत में तेल की कीमत और भी बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचेगा। इससे भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होगा। इसलिए अमेरिका को भारत की मजबूरियां समझते हुए ईरान के साथ तेल का आयात जारी रखने देना चाहिए।

● *शुभम गुप्ता, नावागढ़, धनबाद*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com